Cost for creating irrigation capacity in Madhya Pradesh

1200. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the cost for creating per hectare irrigation capacity through the minor projects is less as compared to the major and medium projects of Madhya Pradesh as on date;

(b) if so, the details thereof;

(c) the measures being taken to encourage minor irrigation projects during the Eighth Five Year Plan project;

(d) the targets fixed for major, medium and minor projects separately for creating irrigation capacity during the said plan period; and

(e) the total amount likely to be spent on these projects under the three categories?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Considering only the direct investment, the Minor Irrigation schemes may appear to be cheaper on cost per hectare basis as compared to Major & Medium projects. However, if the proportionate cost of resource to energise the tubewells/pumpsets in Minor irrigation schemes is taken into account, the Minor schemes are not less costly on cost per hectare basis than Major & Minor projects. Moreover, the useful life of Major & Medium projects is longer than the Minor schemes. This is applicable for projects of Madhya Pradesh also.

(c) The main elements of the strategy for the Minor irrigation during the Eighth Five Year Plan inter-alia include (i) priority for speedy completion of large number of ongoing surface water minor irrigation schemes, (ii) encouragement to Minor surface water lift irrigation schemes both individually and community owned, (iii) encouragement to repair and improvement of Minor irrigation tanks as well as the development of new works as part of the integrated micro development of tects, (iv) emphasis on conjunctive use of surface and ground water, (v) priority to the installation of sprinkler/drip irrigation system in water scarce and drought prone areas, (vi) improvement in the utilisation of public tubewells and their rehabilitation and (vii) discouragement to over exploitation of water.

(d) The Eighth Five Year Plan (1992—97) envisages creation of additional irrigation potential to the extent of 4.50 and 5.00 lakhs ha. through Major & Medium surface water irrigation projects and Major irrigation schemes respectively in Madhya Padesh.

(e) During the Eighth Plan period, Rs. 1791.29 crores and Rs. 728.37 crores have been allocated to Major & Medium irrigation projects and minor irrigation schemes respectively in Madhya Pradesh.

जल बांटने के लिये बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता

1201. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश को बिहार के लिये 3 लाख एकड़ फुट जल छोड़ना था जिसे सरकार समय पर नहीं दे रही है और उसी जल को अनुचित रूप से जल-विद्युत निर्माण में प्रयोग कर रही है;

(ख) बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को "फीडर डैम" के निर्माण के बारे में भेजे गये प्रस्ताव की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इसके लिये यह आदेश देने का विचार रखती है कि इस

संबंध में किये गये समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को तीन लाख एकड़ फुट जल को अक्तूबर से मार्च की अवधि में छोड़ना होगा;

(घ) क्या सरकार कदवन (बिहार) में "फीडर डैम" बनाने का प्रस्ताव रखती है ? और यदि हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) :

(क) और (ग) रिहन्द बांध विद्युत उत्पादन के लिए वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सितम्बर, 1993 के द्विपक्षीय समझौते के जरिए बिहार राज्य सरकार ने अक्टूबर में मोन बराज के अंतर्गत सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल के रूप में रिहन्द जलाशय भण्डारण के 3 लाख एकड़ फुट के आरक्षण का अनुरोध किया। इसमें यह भी तय किया गया कि दोनों राज्य सरकारों के विचारार्थ वित्तीय पहलुओं सहित विस्तृत सिफारिशें दोनों राज्य सरकारें तैयार करेंगी। चूंकि दोनों राज्य सरकारों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने रिहन्द जलाशय में जल की उपलब्धता बिहार में सिंचाई आवश्यकता तथा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत का अनुमान लगाने के बाद रिहन्द जलाशय के प्रचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु अक्तूबर, 1992 में संयुक्त प्रचालन समिति गठित की ताकि दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नवम्बर, 1993 में समिति ने यह निर्णय लिया कि अक्तूबर के दौरान बिहार की सिंचाई मांगों पर रिहन्द जलाशय की प्रचालन अनुसूची को तैयार करने हेतु रिहन्द समझौते के अनुसार विचार किया जाये। यह भी सहमति हुई कि रिहन्द जलाशय में जल उपलब्धता की स्थिति का जायजा लेने तथा वर्ष की वास्तविक प्रचालन योजना निर्धारित करने हेतु संयुक्त प्रचालन समिति के सदस्यों की बैठक प्रत्येक वर्ष सितम्बर में होगी।

(ङ) और (च) केन्द्रीय जल आयोग में जून, 1990 में प्राप्त कदवान जलाशय परियोजना रिपोर्ट की जांच करने के बाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में जलमग्नता, जल विज्ञान को पुष्ट करने, एकीकृत बहु प्रयोजनी परियोजना तैयार करने और पर्यावरणिक तथा वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने जैसे मुद्दों को हल करने के लिए जुलाई 1990 में इसे बिहार राज्य सरकार को लौटा दिया गया। परियोजना का निर्बाधन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की संतोषजनक रूप से अनुपालना करती है

Subarnarekha Canal Project (Orissa)

1202. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the progress made and the present status of the Subarnarekha Canal Project (Orissa);

(b) the original targetted date of its completcon, and present target date of completion; and

(c) the details of World Bank aid received and sanctioned and the details of work undertaken so far for the rehabilitation of the persons whose land has been acquired alongwith the number of such persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON):

(a) Subarnarekha Irrigation Project (Orissa) estimated to cost Rs. 1013.68 crores including the Orissa share of Rs. 223.36 crores to Bihar for joint works was found accepatable by the Advisory Committee in its meeting held on